बाहर से जितनी मजबूत अंदर से उतनी ही कमजोर है मोदी सरकार

महेंद्र मिश्र

वैसे तो पूर्ण बहुमत और गठबंधन दलों के समर्थन के चलते मोदी सरकार बेहद मजबूत दिख रही है। लेकिन शायद इतिहास की यह पहली सरकार होगी जो बाहर से जितनी मजबूत दिख रही है अंदर से उतनी ही ज्यादा कमजोर है। यह पहली सरकार है जिसके जनादेश पर सवाल खड़ा हो गया है। और देश के एक बड़े हिस्से में इसको लेकर संदेहों का बाजार गर्म है। और समाज, राजनीति और बौद्धिकों का एक हिस्सा इन संदेहों को लेकर अब निष्कर्ष पर पहुंचने के करीब है। जिसमें एक बड़े हिस्से का मानना है कि बहुमत के आंकड़े के पीछे ईवीएम का खेल है। हालांकि अभी भी उनके पास इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। लेकिन जमीन पर नजर रखने वाले इस हिस्से का मानना है कि मोदी का जनादेश मैनुफैक्चर्ड है। लिहाजा उन्होंने इसके खिलाफ अपने तरीके से गोलबंदी भी शुरू कर दी है। यह बात सही है कि अभी वह सीधे सरकार के खिलाफ केंद्रित नहीं हैं। लेकिन उसमें आखिरी तौर पर सरकार ही घिरेगी।

दरअसल यह मैनुफैक्चरिंग सिर्फ एक स्तर पर नहीं हुई है। बल्कि जिस तरह से चुनाव का संचालन किया गया और उसमें सत्ता पक्ष द्वारा जो मुद्दे सामने लाए गए उसमें भी एक किस्म का छलावा शामिल था। मसलन पूरे चुनाव के दौरान न तो मोदी ने अपने पिछले पांच साल के कार्यकाल पर बात की। और न ही उन्होंने जनता से जुड़े किसी बुनियादी मुद्दे को उठाया। अगर विपक्ष ने कोई कोशिश भी की तो उसे दरकिनार कर दिया गया। और पूरा चुनाव अभियान पाकिस्तान और राष्ट्रवाद के इर्द-गिर्द सिमट कर रह गया। इस रूप में कहा जा सकता है कि ईवीएम की हैकिंग पर तो अभी पड़ताल और जांच जारी है लेकिन जनता के दिमाग को मोदी ने जरूर हैक कर लिया था। राष्ट्रवाद के इस चुनावी नशे से जैसे ही जनता बाहर निकलेगी और उसके अपने रोजी-रोटी के सवाल सामने आएंगे

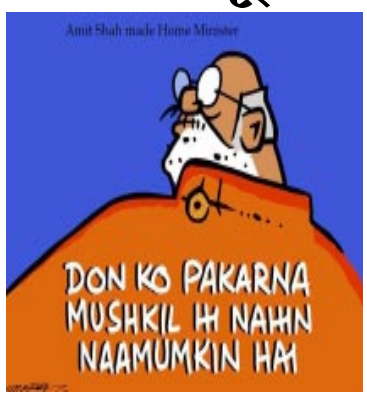

और उसी के साथ सरकार और उसकी नीतियों से उसकी तकरार होगी। असली लड़ाई तभी शुरू होगी।

यह सरकार किस कदर कमजोर है इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उसके पास एक अदद वित्तमंत्री के लिए काबिल चेहरा तक नहीं है। स्वास्थ्य कारणों से अरुण जेटली के अपना नाम वापस लेने के साथ ही पार्टी नये वित्तमंत्री की तलाश में जुट गयी है लेकिन उसे कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। ले- देकर उसके पास पीयूष गोयल हैं जो एक दौर में पार्टी के खजांची रहे हैं और वित्तीय मामलों में उनकी समझ सीए के दायरे से आगे नहीं बढ़ पाती है। लिहाजा एक ऐसे नाजुक मौके पर जबकि देश की अर्थव्यवस्था बेहद संवेदनशील दौर में पहुंच गयी है एक मजबूत, सक्षम और दूरंदेश वित्तमंत्री वक्त की जरूरत थी। लेकिन उसको पूरा करती हुई सरकार नहीं दिख रही है।

विदेश मंत्रालय संभालने के लिए उनके पास उस सुषमा स्वराज के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं दिख रहा है। जिन्हें स्वास्थ्य कारणों से चुनाव नहीं लड़ाया गया। और अब बताया जा रहा है कि शायद उन्हें ही फिर से राज्यसभा के रास्ते से लाकर इस मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी जाए।

वैसे तो राजनाथ का फिर से गृहमंत्री बनना तय माना जा रहा है। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि उन्हें स्पीकर के लिए तैयार किया जा रहा था लेकिन उन्होंने उससे साफ-साफ इंकार कर दिया। लिहाजा अभी राजनाथ को कैबिनेट से हटाना भी मुश्किल है इसलिए उन्हें उनके मंत्रालय के साथ ही संतुष्ट किया जा सकता है। हालांकि चर्चा तो अमित शाह के भी गृहमंत्री बनने की है। अगर यह संभव हो जाता है तो मोदी एक तड़ीपार और तमाम संगीन आपराधिक मामलों में आरोपी शख्स को गृहमंत्रालय देने वाले पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये सरकार कितनी मजबूत हुई है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले पांच सालों में अपने शीर्ष चारों मंत्रालयों को भरने के लिए उसके पास सक्षम चेहरे तक नहीं हैं।

शपथ ग्रहण समारोह में मेहमानों की भागीदारी और उसमें शामिल होने वालों की सूची के मसले पर पहले ही विवाद खड़ा हो गया है। वैसे तो यह पूरा संवैधानिक आयोजन होता है। जिसमें किसी भी तरह की राजनीति को बीच में नहीं आने देना चाहिए। क्योंकि यह किसी पार्टी की नहीं बल्कि एक ऐसी सरकार के गठन का मौका होता है जो सबको लेकर साथ चलने का संदेश देती है। लेकिन इस मौके को मोदी और उनके सहयोगियों ने जितने तुच्छ राजनीतिक स्वार्थों की भेंट चढ़ा देने की कोशिश की है वह अपने आप में बेमिसाल है।

उन्होंने बंगाल से राजनीतिक हत्या के पीड़ितों को समारोह में बुलाकर पूरे आयोजन को राजनीतिक बना दिया। और एक बड़े मौके को बेहद छोटी राजनीति की भेंट चढ़ा दिया। इससे ममता बनर्जी जिन्होंने पहले आने की सहमति दी थी अब इंकार कर दिया है। सचमुच में अगर मोदी-शाह को लग रहा था कि राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों को यहां प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए तो फिर उन्हें दोनों पक्षों के पीड़ितों को बुलाना चाहिए था जिसमें तृणमूल और दूसरे दलों के लोग भी शामिल हैं। लेकिन ऐसा न करके बीजेपी ने अपनी तुच्छ राजनीति का ही परिचय दिया है।

यही हाल उसने कांग्रेस शासित राज्य सरकारों के साथ भी किया है। अभी चुनाव नहीं खत्म हुए थे कि उनके विधायकों की खरीद-फरोख्त और सरकारों के गिराने की कवायद बीजेपी ने शुरू कर दी। और यह काम कर्नाटक, एमपी और राजस्थान में अपने चरम पर है। ऐसे में उन सरकारों के प्रतिनिधि आपके किसी समारोह में भला क्यों भाग लेना चाहेंगे। लिहाजा उन्होंने भी आने से इंकार कर दिया है।

इस बात में कोई शक नहीं कि जनता के बुनियादी सवालों के हर मोर्चे पर फेल होने वाले मोदी का एक ऐसा मोर्चा है जिस पर वह कभी भी नाकाम नहीं हो सकते हैं। वह है इवेंट का आयोजन। एक बार फिर उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह को कुछ इसी तरह का मौका बना दिया है। जिसमें उन्होंने बिम्स्टेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया है। और इसके जरिये पिछले शपथ ग्रहण के मुकाबले एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश की है। गौरतलब है कि पिछले शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने सार्क देशों के देशों को ही आमंत्रित किया था। कुछ लोग मजाक-मजाक में ही सही कह रहे हैं कि अगले शपथ ग्रहण में मोदी जी जी-20 के देशों को बुलाएंगे।

इस तरह के इवेंट और इन बड़े आयोजनों से लोगों को कुछ दिनों तक के लिए संतुष्ट किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही जनता को अपनी जिंदगी की सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ेगा ये सारे इवेंट हवा हो जाएंगे। लिहाजा मौजूदा मोदी सरकार सत्ता में आने के साथ ही कई कसौटियों पर खड़ी हो गयी है। इनमें वह कितनी खरी उतरती है उसको जानने के लिए कुछ वक्त आपको और देना पड़ेगा।

सुधी पाठक इस पर भी जरूर गौर करें

गोदी मीडिया सत्ता की गोद में बैठ कर खबरों को दबाने व भ्रमित करने का काम कर रहा हो तो 'मज़दूर मोर्चा' जैसे वैकल्पिक मीडिया को मजबूत करना आज की जरूरत है। पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान सुधी पाठकों ने देखा होगा कि आपका यह छोटा सा मोर्चा किसी राजनेता का भोंपू नहीं बना, किसी का यशोगान नहीं किया और न ही किसी के विज्ञापन छापे।

'मज़दूर मोर्चा' केवल पाठकों के सहयोग से चलने वाला साप्ताहिक है। पाठक ही इसके संवाददाता हैं और पाठक ही संरक्षक। आपका यह साप्ताहिक और अधिक एवं सटीक खबरें आप तक पहुंचा सके इसके लिये आपके आर्थिक सहयोग की सख्त जरूरत है। 'मज़दूर मोर्चा' एक व्यक्ति से 100 रुपये चंदा लेने की अपेक्षा सौ लोग़ों से एक-एक रुपये का सहयोग लेना अधिक पसंद करता है। अतः अपनी आवाज़ को बुलंद करने व दबी-छिपी तमाम खबरों को जानने के लिये 'मज़दूर मोर्चा' को यथा-शक्ति आर्थिक सहयोग करें।

खबरों को संकलित करने के लिए कम से कम एक लैपटॉप की सख्त आवश्यकता है। समर्थ पाठक इस दिशा में सहयोग करें तो बड़ी मेहरबानी होगी।

धन्यवाद। -सम्पादक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में

खाता संख्या : 451102010004150, IFSC CODE : UBIN0545112

गतांक की चीर-फ़ाड़

छात्राओं के यौन शोषण के गंभीर आरोप

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

मज़दूर मोर्चा के 26 मई-1 जून 2019 के अंक में राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, साहित्यक व शैक्षिक मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशित हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय संविधान की संवैधानिक व्यवस्थाओं को दर किनार करते हुए सत्रहवीं लोकसभा का चुनाव संसदीय प्रणाली की जगह अमेरिका की तरह अध्यक्षीय प्रणाली की तौर पर लड़ा। पुलवामा कांड के बाद पाकिस्तान में बालाकोट एयर स्ट्राइक से मोदीजी की छवि ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में पुख्ता की गई जो दुश्मन के घर में घुसकर जवाब देने की क्षमता रखता है, जिससे राष्ट्रवाद का ऐसा मुद्दा बना, जिसकी काट विपक्ष आखिर तक तलाश नहीं कर पाया। आरएसएस, भाजपा व मोदीजी ने हिंदू धर्म का मुद्दा खुलकर उछाला और हिन्दुत्व की विचारधारा का कार्ड खेलकर मोदीजी को हिन्दुओं का रक्षक जाहिर कर दिया। दोनों मुद्दों पर चुनाव आयोग व आचार संहिता की अवहेलना में कोई कसर नहीं छोड़ी गई।

राफ़ेल करार पर बिना हस्ताक्षर का हल्फनामा पेश करके तथा सीएजी की तथाकथित रिपोर्ट का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को प्रभावित करके मोदी सरकार ने निर्णय को क्लीन चिट को सफलतापूर्वक प्रचारित किया तथा राफ़ेल पर कोर्ट सुनवाई की जो रिपोर्ट मीडिया के जरिए जनता तक गई, उससे यह धारणा बनाई गई कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाए। मोदी सरकार की योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्जवला योजना, शौचालय निर्माण योजना, जन-धन योजना आदि फ़ायदा लेने वाला गरीब तबका भी मोदी जी से जुड़ गया। मीडिया विशेषकर इलैक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी ने मोदीजी व राहुल गांधी के बीच पक्षपात किया और राहुल गांधी के मुकाबले में मोदीजी को तीन गुणा समय दिया तथा मोदी जी के चुनाव प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

'विपक्ष के पास है बड़ा जनाधार' के जरिये वर्तमान लोकसभा चुनाव के दौरान मीडिया, आर्थिक पक्ष, विपक्ष का बिखराव, आरएसएस, हिन्दुत्व की विचारधारा आदि की भूमिका का सटीक विश्लेषण किया गया है। उचित निष्कर्ष निकाला गया है कि इस चुनाव में राज्य स्तरीय राजनीति का जनता के मतदान-व्यवहार पर असर लगभग समाप्त हो गया है तथा नागरिक समाज के विभिन्न तबकों पर आरएसएस की पकड़ मजबूत हो

दूसरी तरफ़ कांग्रेस व राहुल गांधी का फ़ोकस 'चौकीदार चोर है' के नारे पर इतना ज्यादा हो गया कि वह अपने घोषणा पत्र की अच्छी बातों जैसे न्याय, रोजगार, किसानों के हित आदि की योजनाओं को जनता तक नहीं पहुंचा सके। राहुल गांधी धर्म निरपेक्षता व सहिष्णुता तथा बहुलवादी विचारधारा की बजाए सोफ्ट हिन्दुत्व का कार्ड खेलकर भाजपा व मोदी जी के जाल में फ़ंस गये और जनता सोफ्ट हिन्दुत्व व भाजपा के हिंदुत्व के बीच चकराकर भाजपा व मोदीजी के हिंदुत्व की विचारधारा की ओर झुक गई। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष का एक नारा 'मोदी हटाओ' रहा लेकिन विपक्ष मोदी जी का विकल्प बनने की संभावना नहीं जगा सका, जिससे वोटर उलझकर मोदीजी की तरफ़ आकर्षित हो गया। भाजपा के मुकाबले में कांग्रेस के चुनाव लड़ने के लिये आवश्यक कुशल संगठन, कार्यकर्ता, प्रबंधन व प्रोफ़ेशनलिज़्म का अभाव नज़र आया।

चुकी है और उसकी हिंदुत्व की विचारधारा ने विरोधी विचारधारा को कमजोर कर दिया है।

चुनाव परिणाम के बाद भाजपा के संसदीय दल की बैठक में मोदीजी ने सहिष्णुता व सबका साथ, सबका विकास तथा सबका विश्वास की बात तो की लेकिन मोदी भक्त व समर्थक अतिउत्साहित होकर निष्पक्ष पत्रकारिता का कर्त्तव्य निभाने, जनता की समस्या से रू-बरू कराने तथा साम्प्रदायिकता व असहिष्णुता के खिलाफ़ बोलने वाले पत्रकारों जैसे रवीश कुमार को जलील व अपमानित करने का प्रयास करते रहते हैं, जिसको 'क्या 2019 के चुनाव में मैं भी हार गया हूं' में उज़ागर किया गया है।

अब समय की आवश्यकता है कि धर्म निरपेक्षता, सहिष्णुता, बहुलवादी, विभिन्नता में एकता, वैज्ञानिक सोच व उदारवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग तथा स्वस्थ व निष्पक्ष पत्रकारिता का धर्म निभाने वाले साहसी व निडर पत्रकार एकजुट होकर आपसी सहयोग से सशक्त जनमत का निर्माण करे।

विश्वविद्यालयों के अधिकारियों, प्रोफ़ेसरों व अन्य स्टाफ़ की मीलीभगत से नकल का धंधा और पैसे आदि का लेन-देन तो हरियाणा के अधिकतर कॉलेजों में बहुत सालों से चल रहा था और उसमें कुछ लोग मोटा पैसा वसूल रहे थे। इसलिए यही लोग बार-बार परीक्षा केन्द्र में सुपरिटेंडेंट तथा फलाइंग स्क्वाड में अपनी ड्यूटी लगवाते थे। इससे भी शर्मनाक बात तो तब गई जब नकल के एवज में छात्राओं का यौन शोषण होने के आरोप लगने लगे। दैनिक समाचार पत्रों व सोशल मीडिया में प्रोफ़ेसरों की आपसी गुटबाज़ी की शिकार स्थानीय राजकीय महिला महाविद्यालय की छात्रा के यौन उत्पीड़न का मामला सुर्खियों में है। विभिन्न संगठनों व संस्थाओं द्वारा आरोपित एसोसिएट प्रोफ़ेसर चंद्र शेखर वशिष्ठ, लैब एटेंडेंट जगदेव व चपरासी विक्रम के विरुद्ध प्रदर्शनों का दौर जारी है।

छात्राओं के यौन शोषण के गंभीर आरोप महज इन दो कॉलेजों तक ही सीमित नहीं लगते हैं, बल्कि अन्य कॉलेजों में भी ऐसे संगीन मामले होने की संभावना है। इनकी रोकथाम के लिये आवश्यक है कि राज्य की खट्टर सरकार एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष व्यापक जांच समिति का गठन करे जो सभी कॉलेजों विशेषकर महिला कॉलेज व सह-शिक्षा कॉलेजों के ढांचे की जांच करे।

अक्टूबर-नवम्बर तक होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में हरियाणा के सभी 10 सीटों पर भाजपा का कब्जा होने के बाद पड़ने वाले प्रभाव का 'खट्टर की रहनुभाई में सभी सीटें जीतने का असर विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा-राज्य की सभी 10 सीटों का गठन विश्लेषण' में आकलन किया गया है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि भाजपा की खट्टर सरकार गैर-जाट बिरादरी का ध्रुवीकरण करने में कितना सफ़ल होती है तथा कांग्रेस आपसी गुटबाज़ी के चक्कर से कितना उबर पाती है।

आजकल अभिभावकों में अपने बच्चों को डॉक्टर व इंजिनियर बनाने की होड़ मची हुई है और इसके लिये प्रतिस्पर्धा बनी रहती है कि किसका बच्चा कौन से कोचिंग सैंटर में जाता है। वे बच्चे की रुचि का कोई ध्यान नहीं रखते, बल्कि अपनी महत्वकांक्षा का उनको शिकार बना देते हैं। छात्र इन कोचिंग सेंटर के डिप्रेशन व स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पाते। परिणामस्वरूप, उनमें से कई आत्महत्या जैसा अंतिम कदम उठाने को विवश हो जाते हैं, जिसकी 'कोटा में आत्महत्या करने वाली छात्रा कृति ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था ....' के जरिये व्याख्या की गई है। बच्चों की आत्महत्या रोकने का उपाय है कि अभिभावक अपने बच्चों की पसंद व रुचि को महत्व दे न कि आपसी महत्वकांक्षा उन पर थोपे। 'मोदी केदारनाथ में-प्रभो! केदारनाथ से मेरा पुराना नाता है आपसे भी पहले मैं यहां तपस्या कर चुका हूं' 'सर आगे की गुफ़ा बहुत छोटी है, बस एक आदमी जा सकता है...-नहीं...एक कैमरामैन तो और आना ही चाहिये...' कार्टूनों के जरिए मोदीजी की केदारनाथ गुफ़ा में तपस्या का मीडिया द्वारा प्रचारित व प्रसारित करने पर उपयुक्त तंज कसा गया है।

इसी दौरान छात्रा ने एक और सीडी जारी कर पड़ोसी नेहरू कॉलेज में भी यौन शेषण के धंधों का आरोप लगाया है जो पिछले दस वर्ष से चल रहा है, जिसमें एक पुरुष और तीन महिला प्राध्यापक शामिल हैं। इस पर प्रिंसिपल प्रीता कौशिक ने मिटिंग बुलाकर उसमें खुलासा किया कि उस पुरुष प्रोफ़ेसर का नाम तत्कालीन प्रोफ़ेसर तथा वर्तमान तिगांव राजकीय महाविद्यालय में प्रिंसिपल इकबाल सिंह बताया, जिसका 'राजकीय महिला कॉलेज फ़रीदाबाद में-कर्मचारी द्वारा नकल के बदले सेक्स प्रकरण' में पर्दाफाश किया गया है। आश्चर्य है कि प्रिंसिपल कौशिक की इस रिपोर्ट पर उच्चतर शिक्षा विभाग और विभिन्न संस्थान व संगठन जो प्रोफ़ेसर वशिष्ठ के मामले में सक्रिय हैं ने रहस्यमय चुप्पी साध रखी है। इससे सबका दोगलापन जाहिर होता है।

स्थानीय राजकीय महिला महाविद्यालय में छात्रा के यौन शोषण के प्रकरण के संदर्भ में कॉलेज के स्टाफ़ व छात्राओं से बात-चीत के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई। इस आधार पर 'महिला कॉलेज में शोषण, खुलासों के बावजूद शतुरमुर्ग बनी रही खट्टर सरकार' में इस मामले की असलियत का खुलासा किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे मामले में आपसी गुटबाजियां साफ़ तौर पर दिखाई दे रही थीं।